विरासत बची रहे

विख्यात नोत्र देम चर्च की ऐतिहासिक इमारत में लगी आग से दुनियाभर में गहरी उदासी का माहौल है. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रां ने पेरिस के इस चर्च को उचित ही अपने देश का 'इतिहास, साहित्य और कल्पना' कहा है. ऐसी इमारतें अतीत का प्रतीक होने के अलावा मनुष्य की उन भावनाओं और क्षमताओं की उत्कृष्टता को भी प्रतिबिंबित करती हैं, जिनके आधार पर हम सभ्यताओं और संस्कृतियों को गढ़ते हैं. इसीलिए जर्जर भवनों और खंडहरों को भी सहेजा जाता है. यह सहेजना बीते हुए के प्रति आभार है और आगत के लिए उत्तरदायित्व का भाव. पेरिस के केंद्र में स्थित करीब हजार साल पुराने भवन के पुनर्निर्माण के लिए सरकार और समाज ने जो पहलें की हैं, वह प्रेरणादायी है. हमें भी अपने देश की ऐतिहासिक इमारतों के रख-रखाव और बचाव के लिए सचेत होना चाहिए. ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय मूल के प्रतिष्ठित संग्रहालय विशेषज्ञ विनोद डैनियल ने निवेदन किया है कि भावी सरकार को कार्यभार संभालते ही आग से स्मारकों की सुरक्षा की व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा करनी चाहिए. इस प्रयास में राज्य सरकारों की भी महती भूमिका है, क्योंकि हजारों इमारतों की जिम्मेदारी उनके पास भी है. विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में एक भारतभूमि को सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक धरोहरों की बेमिसाल पूंजी मिली हुई है. स्मारकों से देश का कोना-कोना आबाद है. ये इमारतें हमारे इतिहास के विभिन्न काल-खंडों का अध्याय हैं, संस्कृतियों के समुच्चय और सहभागिता का उदाहरण हैं तथा पुरखों के गौरव का महाकाव्य हैं. दुर्भाग्य से हम इस विरासत की देखभाल में लापरवाह हैं. वैसे तो देशी-विदेशी सैलानी बड़ी संख्या में इमारतों को देखते-सराहते हैं, पर पर्यटकों के लिए आकर्षक इमारतों की संख्या बहुत कम है. इसका एक नतीजा यह है कि कुछ स्मारकों पर हम बहुत अधिक ध्यान देते हैं, लेकिन बाकी को उनके हाल पर छोड़ देते हैं. इतिहास बता रही इमारतों को हम नुकसान पहुंचाने से भी बाज नहीं आते. जिन पर हमारा ध्यान भी है, तो उनकी सुरक्षा का इंतजाम नहीं है. साल 2016 में दिल्ली में प्राकृतिक विज्ञान का राष्ट्रीय संग्रहालय आग में तबाह हो गया था. देश की राजधानी में होने के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका था. पुराने पुस्तकालयों और संग्रहालयों में न तो पानी की ठीक व्यवस्था है और न ही किसी संकट में अमूल्य पांडुलिपियों एवं संस्करणों को बचाने की आपात योजना है. तोड़-फोड़ और अतिक्रमण के कारण भी बड़ी संख्या में इमारतें नष्ट हो रही हैं. धरोहरों को बचाने के लिए कानूनों की कमी नहीं है, पर बेहद कम निवेश, प्रबंधन की अक्षमता और निगरानी में लापरवाही जैसी चिर समस्याएं आड़े आ जाती हैं. नोत्र देम की आग के दो दिन बाद 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया गया है. आनेवाली पीढ़ियों के प्रति हम सबकी जवाबदेही है कि विरासती स्मारकों को आग और अन्य आपदाओं से बचाकर रखें.

धरोहरों को बचाने के लिए कानूनों की कमी नहीं है, पर बेहद कम निवेश, प्रबंधन की अक्षमता और निगरानी में लापरवाही जैसी चिर समस्याएं आड़े आ जाती हैं.

कम होती खाद्य मुद्रास्फीति की चुनौती

अजीत रानाडे
सीनियर फेलो, तक्षशिला इंस्टीट्यूशन
editor@thebillionpress.org

मार्च के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मुद्रास्फीति की दर 2.6 प्रतिशत है. मार्च में समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष के लिए औसत मुद्रास्फीति दर भी लगभग 3.5 प्रतिशत ही है. ये आंकड़े इस क्षेत्र में सफलता की अपनी ही कहानी बयान करते हैं, जिसका श्रेय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) तथा एनडीए सरकार को संयुक्त रूप से दिया जाना चाहिए. सिर्फ तीन वर्ष ही गुजरे हैं, जब आरबीआइ ने मुद्रास्फीति को लक्षित करना आरंभ किया और यह नीति प्रभावी होती प्रतीत होती है. मुद्रास्फीति की दर की गणना कई कारकों को मिलाकर की जाती है, जिनमें वस्तुएं एवं सेवाएं भी शामिल हैं, जिन्हें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) भी कहते हैं. इसे याद करें कि नवंबर 2013 में सीपीआइ मुद्रास्फीति 12 प्रतिशत की चोटी पर पहुंच चुकी थी, जो पिछले दशक का सबसे ऊंचा आंकड़ा था.

सीपीआइ की गणना में ली जानेवाली आधी सामग्रियां तो खाद्य तथा पेय पदार्थों से संबद्ध हैं. इसमें भी खाद्य सामग्रियों को 46 प्रतिशत भारिता (वेटेज) दी जाती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में उसे और भी ऊंचे स्तर की यानी 54 प्रतिशत भारिता दी जाती है. इसलिए जब मुद्रास्फीति में गिरावट का रुझान रहता है, तो इसमें खाद्य मुद्रास्फीति की गिरावट एक बड़ी भूमिका निभाती है. यह एक तथ्य है कि फरवरी के पहले के पांच महीनों के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति नकारात्मक ही थी. मार्च की खाद्य मुद्रास्फीति शून्य से कुछ ही ऊपर 0.3 थी. पिछले पूरे वित्तीय वर्ष के लिए खाद्य मुद्रास्फीति 0.1 पर थी, जो 1991 के बाद की अवधि में न्यूनतम है.

खासकर शहरी उपभोक्ताओं के लिए निम्न तथा स्थिर मुद्रास्फीति खुशी की वजह होती है. विकसित देशों में जहां शहरी आबादी पूरे देश की 90 प्रतिशत अथवा उससे भी ऊपर तक होती है, खाद्य मूल्य वस्तुतः निम्न तथा स्थिर स्तर पर कायम रहते हैं. मगर, भारत जैसे देश के लिए जहां आज भी 50 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्षतः अथवा परोक्षतः कृषि से संबद्ध है, निम्न एवं नकारात्मक खाद्य मुद्रास्फीति का अर्थ यह होता है कि इन परिवारों की आय भी निम्न स्तर पर है. अन्य गैर-खाद्य सामग्रियों के विपरीत, कीमतें गिर जाने पर खाद्य सामग्रियों की मांग तेजी से बढ़ नहीं जाती है. इसलिए गिरती कीमतें साधारणतः किसानों की आय घटने की ही सूचक होती हैं, न कि कृषि उत्पादन में वृद्धि की. खाद्य सामग्रियों में भी जिन चार श्रेणियों की कीमतों में सर्वाधिक गिरावट हुई है, वे हैं फल, सब्जियां, दालें एवं चीनी. इन चारों की सम्मिलित भारिता 15 प्रतिशत है. इनकी कीमतें अंशतः तो जरूरत से ज्यादा आपूर्ति की वजह से गिरी हैं. एक वक्त वह भी था, जब हमें दालें आयात करनी पड़ती थीं. पिछले तीन वर्षों में खाद्यान्नों का उत्पादन भी लगातार बढ़ा है.

> शून्य के करीब खाद्य मुद्रास्फीति यह संकेत करती है कि शहरी बनाम ग्रामीण व्यापार संतुलन एक ओर अत्यधिक झुक चुका है, जिसे विपरीत किये जाने की जरूरत है.

कम कीमतें तथा किसान परिवारों में कम आय ही वे वजहें थीं, जिनसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू करने का विचार उत्पन्न हुआ. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भी किसानों को कुल उत्पादन लागत के 50 प्रतिशत का मुनाफा देने पर लक्षित है. पर यह प्रत्याशित ढंग से प्रभावी सिद्ध न हो सका, क्योंकि तंग राजकोषीय स्थिति की वजह से केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा उपज की खरीद काफी कम ही रही. यही कारण है कि सरकार भी अत्यंत निम्न खाद्य मुद्रास्फीति के निहितार्थों से चिंतित है.

ऐतिहासिक रूप से भारत की औद्योगीकरण नीति में शहर समर्थक एवं कृषि विरोधी पुट रहा है. नतीजतन, व्यापार की शर्तें उद्योग की तुलना में कृषि के विरोध में ही झुकी रही हैं. यदि किसान परिवारों की तादाद में एक बड़ी गिरावट आयी होती और कृषि उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ा होता, तो हमें इन दो स्थितियों के सम्मिलित फायदे हासिल हुए होते. पर दुर्भाग्यवश कृषि के बाहर किसी सुरक्षित जॉब के अभाव के कारण किसान कृषि क्षेत्र को छोड़ नहीं सके. एक गतिविधि के रूप में कृषि स्वयं ही कई बंधनों में जकड़ी है, जिनके उदाहरण में मूल्य एवं मात्रा नियंत्रणों, कृषि बाजार समितियों तथा बटाईदारी खेती से संबद्ध पुरातन कानूनों के चंगुल, महाजनों का नियंत्रण और कॉरपोरेट-किसान संबद्धता की सीमाओं को लिया जा सकता है. खेतों से खाने तक की मूल्य श्रृंखला को कृषि प्रसंस्करण, शीतगृहों, खुदरा सुपर बाजारों के विस्तार तथा मूल्य वर्धित उत्पादों की दरकार होती है, जिनकी संभावनाएं अभी भी सुदूर ही हैं.

हालांकि, हम कृषि में सार्थक आर्थिक सुधारों के इंतजार के साथ ही विनिर्माण, खनन, रियल एस्टेट, निर्माण एवं सेवा क्षेत्र में जॉब के भारी सृजन की राह अब भी ताक ही रहे हैं, ताकि ये सब मिलकर कृषि से अतिरिक्त श्रमबल सोख सके, फिर भी हमारे द्वारा यह सवाल तो किया ही जाना चाहिए कि क्या लगभग शून्य खाद्य मुद्रास्फीति हमें स्वीकार्य हो सकेगी? कुछ वर्ष पहले आरबीआइ के शोध विभाग ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसके अनुसार भारत में आर्थिक विकास की रफ्तार तेज करने के लिए इसकी मुद्रास्फीति दर पांच प्रतिशत के लगभग होनी चाहिए. इसलिए मुद्रास्फीति की शून्य दर तो निश्चित रूप से अत्यंत निम्न है. मुद्रा अवस्फीति अंततः मुद्रा अपस्फीति (डिफ्लेशन) को तथा मूल्य प्रत्याशाओं की एक अधोगामी श्रृंखला को ही जन्म देती है. यदि लोग यह उम्मीद करते हैं कि कीमतें और भी नीचे जायेंगी, तो वे खरीद को टालते हैं, जिससे मांग में कमी आती है और जिंसों का भंडार बढ़ता जाता है, जो कीमतों में और भी कमी पैदा करता है. ऐसी स्थिति एक विकासशील देश के लिए खतरनाक होती है. यदि खाद्य मुद्रास्फीति बहुत कम हो गयी, तो हमें अविलंब गैर-कृषि गतिविधियों या नकदी के ट्रांसफर से कृषि आय बढ़ाने के रास्ते तलाशने होंगे.

आधिकारिक अनुमानों के मुताबिक, इस वक्त भारत का 42 प्रतिशत हिस्सा सुखाड़ की चपेट में है. ऐसे में फल तथा सब्जियों के दाम तेजी से बढ़कर खाद्य मुद्रास्फीति के परिदृश्य में नाटकीय परिवर्तन ला सकते हैं. कृषि उत्पादन में कमी से अधिक आपूर्ति की स्थिति में भी कमी आ सकती है. हालांकि, चीनी की कीमतों में वृद्धि की कोई संभावना नहीं है. यदि खरीद की मात्राओं में पर्याप्त बढ़ोतरी लाते हुए एमएसपी से संबद्ध नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाये, तो कृषि संकट में कुछ कमी लायी जा सकती है. शून्य के करीब खाद्य मुद्रास्फीति यह संकेत करती है कि शहरी बनाम ग्रामीण व्यापार संतुलन एक ओर अत्यधिक झुक चुका है, जिसे विपरीत किये जाने की जरूरत है.

(अनुवाद : विजय नंदन)

चीन के निर्यात का गिरता ग्राफ

डॉ अश्वनी महाजन
एसोसिएट प्रोफेसर, डीयू
ashwanimahajan@rediffmail.com

> निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था होने के कारण पिछले काफी समय से घटते निर्यातों ने चीन की नींद उड़ा दी है. आर्थिक रूप से चीन का गिरता ग्राफ उसे कहां ले जायेगा, यह तो समय ही बतायेगा.

लगभग दो दशक से सबसे तेज अर्थव्यवस्था के रूप में ही नहीं, बल्कि 'मैन्युफैक्चरिंग हब' के रूप में स्थापित होता चीन, आज संकटों से गुजर रहा है. चीन के मॉडल को दुनिया के कई देश एक आदर्श के रूप में मान रहे थे. अब उन्हें सोचना पड़ेगा कि क्या चीन वास्तव में एक आदर्श अर्थव्यवस्था है? चीन मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ा, तो दूसरे मुल्क इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, वस्तुओं, मशीनरी, केमिकल्स, दवाईयों, कच्चे माल आदि के लिए चीन पर निर्भर होते गये. उन देशों में रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया, क्योंकि चीनी उत्पादों के कारण उनके उद्योग बंद होते गये. भारत, अमेरिका, यूरोप और अन्य कई देशों के औद्योगीकरण को बड़ा धक्का लगा.

भारी निर्यातों और व्यापार में अतिरेक के चलते चीन का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने लगा, जिसके बलबूते चीन ने दूसरे मुल्कों में काफी मात्रा में भूमि खरीदी और इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में भारी निवेश किया. पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सड़क निर्माण, श्रीलंका में हंबनटोटा बंदरगाह समेत कई स्थानों पर चीन द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश इसके उदाहरण हैं. चीन दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में दिखायी देने लगा. लेकिन, आज उसकी जीडीपी ग्रोथ घट रही है. विदेशी व्यापार में धीमेपन के कारण विदेशी मुद्रा भंडार घटकर चार हजार अरब डॉलर से अब तीन हजार अरब डॉलर रह गया है. चीन की कई कंपनियां बंद हो चुकी हैं. पिछले साल चीन के निर्यातों में भी भारी कमी आयी है. कई देशों में अब चीनी आयातों पर आयात शुल्क बढ़ाकर उनको रोका जा रहा है. चीनी हुक्मरान अब कह रहे हैं कि घरेलू उपभोग भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब चीन का विदेशी बाजार सिकुड़ रहा है.

अप्रैल 2018 से दिसंबर 2018 के बीच चीन द्वारा भारत को किये जानेवाले निर्यातों में पिछले वर्ष की तुलना में 6.6 अरब डॉलर की कमी आयी. दुनियाभर में भी चीन के निर्यात अब घटने लगे हैं. दिसंबर 2018 में चीन के निर्यात 4.4 प्रतिशत कम हुए. इसकी वजह व्यापार युद्ध (अमेरिका द्वारा चीनी उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाना) और वैश्विक मंदी को बताया जा रहा है. लेकिन यह पूरा सच नहीं है. साल 2001-02 में जहां चीन के निर्यात मात्र 266 अरब डॉलर ही थे, 2014-15 तक वे 2,342 अरब डॉलर पहुंच चुके थे. उसके बाद वे लगातार घटते हुए 2017-18 में 2,263 अरब डॉलर रह गये. इस साल तो वे और ज्यादा घटनेवाले हैं. दरअसल, चीन बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों का आयात करता है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक सामान तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है. चूंकि इलेक्ट्रॉनिक टेलीकॉम निर्यात प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए चीन से इन कलपुर्जों के आयात में भारी कमी आयी है.

वर्ष 2010 की दिसंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ की दर जो बढ़ते-बढ़ते 12.2 प्रतिशत पार कर गयी थी, वर्ष 2018 की दिसंबर तिमाही तक आते-आते घटकर मात्र 6.4 प्रतिशत ही रह गयी. इसमें ज्यादा नुकसान मैन्युफैक्चरिंग को हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग के महत्वपूर्ण सूचकांक (पीएमआई) में प्रदर्शित भी हो रहा है. फरवरी 2019 तक आते-आते चीन का पीएमआइ सूचकांक 49.2 प्रतिशत पहुंच चुका था. गौरतलब है कि पीएमआइ सूचकांक का 50 से नीचे होना मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट को दर्शाता है. यानी चीन में आयात भी घटने लगा है.

वर्ष 2001 में डब्ल्यूटीओ का सदस्य बनने के बाद, उसके व्यापार नियमों का फायदा उठाकर चीन ने अपने निर्यात काफी बढ़ा लिये थे. वास्तविकता यह है कि चीन अपने निर्यातों को गुपचुप तरीके से सब्सिडी देकर अपनी प्रतिस्पर्द्धा शक्ति बढ़ाने का काम कर रहा था. लेकिन, दुनियाभर में चीनी माल की भारी आवक के चलते जब फैक्टरियां बंद हो गयीं और रोजगार प्रभावित हुआ, तब इन देशों ने आयात शुल्क बढ़ाना शुरू किया. निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था होने के कारण पिछले काफी समय से घटते निर्यातों ने चीन की नींद उड़ा दी है.

चीन ने श्रीलंका में हंबनटोटा बंदरगाह के निर्माण का जिम्मा लिया और इस हेतु श्रीलंका को बड़ा कर्ज भी दिया. कर्ज इतना ज्यादा था कि जिसे श्रीलंका सरकार चुका नहीं पायी और इसके बाद चीन ने श्रीलंका को इस हेतु बाध्य किया कि वह इस बंदरगाह को उसे 99 वर्ष की लीज पर दे दे. श्रीलंका का यह अनुभव बाकी दुनिया के लिए एक नसीहत बन गया है और अन्य देशों को यह लगने लगा है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के नाम पर चीन इन देशों को फांसकर उन्हें अपने ऊपर आश्रित करते हुए उनके लिए खतरा बन सकता है. ऐसे में चीन के साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए समझौते के रास्ते पर जा रहे, या समझौता कर चुके देश अब पीछे हटने लगे हैं. पिछले दिनों मलेशिया के प्रधानमंत्री ने चीन के लगभग 23 अरब डॉलर के समझौतों को हरी झंडी दे दी थी, जिसे अब रद्द कर दिया गया है. बांग्लादेश, हंगरी और तंजानिया ने बेल्ट रोड परियोजनाओं को या तो रद्द कर दिया है या उसके स्वरूप को घटा दिया है. म्यांमार ने चीन को धमकी देकर कि वह उसके समझौते को रद्द कर सकता है, क्यावपीयू बंदरगाह की पूर्व लागत 7.3 अरब डॉलर से घटाकर 1.3 अरब डॉलर पर ले आया है. चीन के साथ पहले साझेदारी और मित्रता निभानेवाला पाकिस्तान भी अब परियोजनाओं का पुनरावलोकन करने लगा है.

इन सभी घटनाओं से स्पष्ट है कि चीन का दुनिया के इन्फ्रास्ट्रक्चर में एक महाशक्ति बनने का सपना धूमिल हो रहा है. आर्थिक रूप से चीन का गिरता ग्राफ उसे कहां ले जायेगा, यह तो समय ही बतायेगा.

बोधि वृक्ष

सद्गुण-दुर्गुण

एक बार की बात है. भगवान कृष्ण ने पहले युधिष्ठिर को एक काम सौंपते हुए कहा- तुम जाओ और एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लाओ जो बहुत दुष्ट हो, जिसमें गुणों का सर्वथा अभाव हो और जो दोषों से पूर्ण हो. फिर भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को अलग बुलाकर आदेश दिया- तुम ऐसा व्यक्ति खोजकर लाओ, जो सद्गुणों से पूर्ण हो, जिसमें एक भी दोष न हो. युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों चले गये और कुछ दिनों के बाद दोनों ही वापस आकर भगवान कृष्ण से अलग-अलग समय में मिले. भगवान कृष्ण ने दोनों से पूछा कि क्या जिस व्यक्ति को खोजने गये थे, उसे ले आये? दुर्योधन कहता है- मैंने ऐसे व्यक्ति को, जो सद्गुणों से संपन्न हो और जिसमें दुर्गुणों का सर्वथा अभाव हो, खोजने का अथक परिश्रम किया, किंतु ऐसा व्यक्ति कहीं भी न मिल सका, जो सर्वथा निर्दोष हो. यदि किसी में एक गुण है, तो उसमें दर्जनों दोष भी हैं. पूरी खोज-बीन के बाद मैंने पाया कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें कोई दोष न हो, तो वह मेरे अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है. अब आप जैसा चाहें, मेरे साथ करें. श्रीकृष्ण मुस्कुराये और बोले- बहुत अच्छा हुआ. दोषों से सर्वथा मुक्त व्यक्ति के दर्शन कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई. युधिष्ठिर के आने पर कृष्ण पूछते हैं- तुम्हारा व्यक्ति कहां है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया- हे प्रभु! संसार का निकृष्टतम पापियों में भी मैंने अनुकरणीय गुण पाये हैं, उनमें भी श्रेष्ठ लक्षण पाये. अतः ऐसा व्यक्ति पाने में मैं सफल न हो सका, जो दोषों से ही पूर्ण हो. प्रत्येक व्यक्ति में कुछ-न-कुछ सद्गुण हैं. तब मैंने अपना अपना विश्लेषण किया और पाया कि मैं दोषों से इतना भरा हुआ हूं कि मैं आपके समक्ष उपस्थित करने के लिए अपने से अधिक उपयुक्त व्यक्ति नहीं पा सका. इन दोनों बातों से यह लगता है कि दृष्टिकोण के ये दो उपर्युक्त दो रूप हैं. युधिष्ठिर का दृष्टिकोण साधक का दृष्टिकोण था. उनमें दोष ढूंढने की प्रवृत्ति बहिर्गामी न होकर अंतर्मुखी थी. आध्यात्मिक मार्ग के हर यात्री के लिए यही आदर्श होना चाहिए.

स्वामी शिवानंद सरस्वती

आपके पत्र

चुनाव में पैसे का खेल

देश में पहली बार पैसे देने के मामले में किसी लोकसभा चुनाव को स्थगित करना पड़ा है. दूसरे चरण यानी 18 अप्रैल को तमिलनाडु के वेल्लोर संसदीय चुनाव को आयोग ने अनिश्चित काल के स्थगित कर दिया है. इससे पहले भी इस राज्य में दो विधानसभाओं आरकेनगर और तंजावुर का चुनाव पैसों के कारण स्थगित कर दिया गया था. ऐसा लगता है कि चुनाव का मतलब पैसा रह गया है. जनसभाओं में लोगों को लाने के लिए पैसे खर्च होते हैं. महिलाओं को साड़ी बांटी जाती है. आयोग बाहुबल और सरकारी अधिकारियों के दुरुपयोग पर तो बहुत हद तक काबू पा लिया है, मगर रुपये की शक्ति के आगे चुनाव आयोग अभी भी कमजोर साबित हो रहा है. आयोग कहता है इस महामारी से लड़ने के लिए मतदाताओं को भी आगे आना होगा. मगर यह कैसे होगा जब देश में गरीबी इतनी अधिक है. लोग एक-एक रुपये के लिए मोहताज हैं.

जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर

फेक न्यूज से वोटर्स रहें सचेत

चुनावी मौसम में सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की बाढ़ आती जा रही है. झूठी खबरों को इस तरह से परोसा जा रहा है कि सही और झूठ का पता ही नहीं चल पाता. आम मतदाता पूरी तरह से भ्रमित होता जा रहा है. जब तक सही स्थिति सामने आती है, तब तक वह पोस्ट अपना असर डाल चुकी होती है. हाल में मुरली मनोहर जोशी का आडवाणी को पत्र काफी वायरल हुआ. बाद में जोशी को इस मामले में चुनाव आयोग को खत लिखना पड़ा कि ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा गया है, इसकी जांच कर कार्रवाई की जाये. सेना के दिग्गजों द्वारा राष्ट्रपति को लिखा गया फेक लेटर भी सोशल मीडिया में काफी वायरल हुआ. फेसबुक और व्हाट्सएप ने अपने स्तर से कदम उठाये हैं लेकिन लोगों को इसके लिए जागरूक करना बहुत जरूरी हो गया है. सरकार को फेक न्यूज से लोगों को सचेत करते रहने की जरूरत है.

अमन सिंह, बरेली, उत्तर प्रदेश

पूरी तरह बैन हो पबजी

कुछ वर्षों से ऑनलाइन गेम के प्रति बच्चों व युवाओं का झुकाव ज्यादा हो गया है. खासकर पबजी आने के बाद प्रायः हर युवा को इसकी लत लग गयी है. चलते-फिरते, खाते-पीते हर वक्त वे गेम में घुसे रहते है. इसका नशा ऐसा है कि रात के तीन-चार बजे तक इसे खेलते रहते है. इस कारण वे पर्याप्त नींद भी नहीं ले पा रहे है. उनके मस्तिष्क, आंख एवं पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है. वास्तविक दुनिया से वे कटते जा रहे हैं और खुद को वर्चुअल दुनिया में कैद कर रहे है. स्थिति इतनी भयावह है कि मना करने पर बच्चे आत्महत्या तक कर ले रहे हैं. यह गेम बच्चों को उनके कैरियर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लगा है. बच्चे व युवा अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता न देकर इस गेम को दे रहे है. आनेवाली पीढ़ी को इस तरह बर्बाद करनेवाले इस गेम के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए. इसे पूरी तरह बैन कर देना चाहिए ताकि हमारे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो.

पीयूष राज, दुमका

कुछ अलग

मोहर लगेगी जात पर!

सुरेश कांत
वरिष्ठ व्यंग्यकार
drsureshkant@gmail.com

शम्मी कपूर की एक फिल्म थी, जिसमें अनाथ होने के कारण वह अपनी प्रेमिका के बात-बात पर गोली मारने की धमकी देनेवाले फौजी बाप के सामने अपने रिश्ते की बात करने जाने के लिए एक भिखारी-दंपती को तैयार करता है, जिनकी भूमिका किन्हीं हास्य-कलाकारों ने निभायी थी. भिखारी को थोड़ी-थोड़ी देर बाद झुककर सलाम करते हुए 'अंधे को भाई साहब!' कहकर भीख मांगने की आदत थी. शम्मी कपूर उन्हें खूब ट्रेनिंग देता है कि फौजी के सामने उन्हें किस तरह पेश आना है और और भिखारी को इस बात की खास ताकीद करता है कि वह भूल से भी फौजी को 'अंधे को भाई साहब!' कहने की भूल न कर दे. तसल्ली होने पर वह उस भिखारी-दंपती को अपनी प्रेमिका के खड़ूस बाप, जो कि दुनिया की सभी प्रेमिकाओं के बाप हुआ ही करते हैं, के पास भेज देता है. भिखारी-दंपती वहां शम्मी कपूर के मां-बाप की भूमिका अच्छी तरह निभा देते हैं और उनके व्यवहार से खुश होकर वह फौजी शम्मी कपूर से अपनी लड़की की शादी करने के लिए तैयार भी हो जाता है, पर ऐन रुखसती के वक्त भिखारी अपने वाली पर आ जाता है और फौजी को झुककर सलाम करते हुए कह बैठता है, 'अंधे को भाई साहब!'

चुनाव में नेता लोग भी विकास, देशभक्ति, जनसेवा आदि की बात करते-करते अपने वाली पर आकर जाति-धर्म के नाम पर वोट मांगने लगे हैं. कोई धर्म-विशेष के लोगों को चेता रहा है कि वे दूसरों के भुलावे में आकर अपने वोट खराब न कर दें, क्योंकि केवल उसे और उसके दल को देने से ही वोट खराब होने से बचते हैं. कोई वोटरों को धमका रहा है कि अगर उनके वोट उसे न मिले, तो फिर उसके पास काम करवाने भी मत आना! किसी को बताना पड़ रहा है कि वह संन्यासी है और अगर उसे वोट न दिये, तो वह अपने पाप उन्हें दे जायेगा और उनके पुण्य हर ले जायेगा. संन्यासी होकर भी किसी के पास पाप एकत्र हो सकते हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर वह दूसरों को ट्रांसफर कर सकता है, पहली बार पता चला. कोई अपने दलित होने के कारण अपने साथ अन्याय होने का रोना रो रहा है, तो कोई अपने पिछड़े होने के कारण अपमानित किये जाने का. उन्हें भरोसा है कि ऐसा करने से वे जनता को अपने साथ हुए कथित अन्याय और अपमान का बदला लेने के लिए उकसा सकेंगे. ऐसा करते हुए वे केंद्रीय चुनाव आयोग की भी परवाह नहीं कर रहे. आचार-संहिता लागू होने के बाद भी काफिले में निकलने पर और एसडीएम द्वारा रोके जाने पर एक नेता ने तो कह भी दिया कि किसके आदेश से रोक रहे हो, चुनाव आयोग आखिर है किसका?

कभी-कभी मैं सोचता हूं कि जाति और धर्म का आविष्कार करनेवाला कितना दूरदर्शी रहा होगा. जाति और धर्म लोगों को आपस में लड़वाने के काम ही नहीं आते, नेताओं को चुनाव जितवाने में मदद भी करते हैं. यही कारण है कि 'न जात पर न पात पर' वाले पुराने नारे के स्थान पर अब तो सबका एक ही सहारा है कि- मोहर लगेगी जात पर!

देश दुनिया से

बेंजामिन नेतन्याहू और दक्षिणपंथ

वर्ष 1920 के दशक से यहूदी आंदोलन दो समूहों में बंट गया था और यहूदी राज्य के प्रतिद्वंद्वी विचार, उदारवादी और दक्षिणपंथी सामने आये थे. डेविड बेन-गुरियन, इस्राइल के संस्थापक और इसके सबसे लंबे समय तक रहनेवाले प्रधानमंत्री, लेबर जियोनिज्म के नेता थे, जिसकी सोच उदारवादी थी. जीव जबोतिंस्की रिविजनिस्ट जियोनिज्म के संस्थापक और दक्षिणपंथी इस्राइली के आध्यात्मिक पिता थे. बेन-गुरियन ने एक स्वतंत्र और समतावादी यहूदी राज्य को मूर्त रूप दिया था. जबकि जबोतिंस्की एक उत्साही यहूदी राष्ट्रवादी थे. फिलिस्तीनियों के साथ टकराव के पूरे आंदोलन को निर्देशित करनेवाले मुख्य कर्ता-धर्ता जबोतिंस्की ही थे. लौह दीवार बनाने की रणनीति उनकी ही थी. इस रणनीति के दो हिस्से थे. पहला, यहूदी सैन्य शक्ति की लौह दीवार का निर्माण कर अरबों को यह मानने के लिए मजबूर करना कि यहूदी राज्य वहां टिके रहने के लिए बना है. दूसरा, फिलिस्तीन में अपने अधिकारों और स्थिति के बारे में अरबों से बातचीत करना. बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने पिछले सप्ताह पांचवी बार चुनाव में जीता है, कई मायनों में जबोतिंस्की के ही उत्तराधिकारी हैं. गौरतलब है कि नेतन्याहू के पिता बेंजियन नेतन्याहू एक दौर में जबोतिंस्की के सचिव थे.

अवी श्लेम

कार्टून कोना

साभार : बीबीसी

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006,
मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है